'यूरोप का पुनः शस्त्रीकरण: संभावनाएं और समस्याएं' विषय पर आईसीडब्ल्यूए की पैनल चर्चा की प्रतिलिपि, सप्रू हाउस, 25 नवंबर 2025

अज्ञात वक्ता: माननीयों, देवियों और सज्जनों नमस्कार। यूरोप का पुनः शस्त्रीकरणः संभावनाएं और समस्याएं विषय पर भारतीय वैश्विक परिषद में होने वाली इस पैनल चर्चा में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूँगा कि कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड पर डाल दें। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की शुरूआत आईसीडब्ल्यूए की कार्यवाहक महानिदेशक और अपर सचिव सुश्री नूतन कपूर महावर जी के स्वागत भाषण से होगी। पैनल चर्चा की अध्यक्षता राजदूत गुरजीत सिंह जी करेंगे, जो जर्मनी, इंडोनेशिया, इथियोपिया, आसियान और अफ्रीकि संघ में भारत के राजदूत रह चुके हैं और आईआईटी, इंदौर में मानद प्रोफेसर हैं।

हमारे पास तीन जाने- माने वक्ता है। हमारे पहले वक्ता हैं रक्षा मंत्रालय के सेना मुख्यालय के पूर्व हथियार और उपकरण महानिदेशक और सामरिक एवं रक्षा अनुसंधान परिषद के प्रतिष्ठित फेलो लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा, इसके बाद अध्यक्ष और जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज़ के जीन मोनेट चेयर और जेएनयू के स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ के अध्यक्ष प्रोफेसर उम्मू सलमा बावा। अगले होंगे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के फेलो डॉ. एलेक्सेई ज़खारोव।

अब मैं सुश्री नूतन कपूर महावर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया अपना स्वागत भाषण दें।

नूतन कपूर महावर: मंच पर मौजूद जाने- माने विशेषज्ञों और मित्रों, सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोप की हथियारों की रणनीति विफल हो गई। सुरक्षा के लिए अकेली सुपरपावर, अमेरिका पर बहुत अधिक विश्वास, देश और बाहरी संबंधों में आर्थिक एजेंडा को सबसे आगे रखना और बाकी विश्व के साथ यूरोप के संबंधों में मानक एजेंडा को आगे बढ़ाने की वजह से रक्षा और सैन्य क्षेत्र में यूरोप सुस्त पड़ गया। यूरोप के अलग- अलग देशों के सैन्यीकरण के तरीकों में बहुत फर्क है, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंग्डम सबसे आगे हैं, और यूरोप के छोटे देश जैसे अल्बानिया और माल्टा बहुत पीछे छूट गए हैं।

यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोप में जो वर्तमान स्थिति है और दूसरी बड़ी शक्तियों के साथ उसके संबंध भी काफी हद तक खराब हो चुके हैं। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की सुरक्षा और बचाव के मामले में एक बड़ा परिवर्तन शुरू किया है। कुछ लोग इसे 'भू- राजनीतिक पुनरुत्थान' कह रहे हैं जिसका पहला असर 2008 के रूस- जॉर्जिया युद्ध में देखने को मिला था।

यूरोप अब मैदान- ए- जंग में है। इस 'भू- राजनीतिक पुनरुत्थान' के कारण। यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई और व्हाइट हाउस के अस्थिर प्रशासन के दोहरे झटकों ने ब्रुसेल्स और यूरोप की राजधानियों में दशकों की लापरवाही को समाप्त कर दिया है और आखिरकार उन्हें आज की वास्तविकता का सामना करने के लिए विवश कर दिया है।

यूरोप में कुल रक्षा खर्च में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है जिसमें पोलैंड, तीन बाल्टिक देश और जर्मनी जैसे देश मुख्य रूप से इस सैन्यीकरण को आगे बढ़ा रहे हैं। अप्रैल 2025 की एसआईपीआरआई (SIPRI) रिपोर्ट में कहा गया है कि यूरोप में जारी पुनः- शस्त्रीकरण के कारण 2024 में विश्व भर में रक्षा खर्च में बढ़ोतरी होगी। लगभग सभी यूरोपियन देशों में कुल मिलाकर 17% की वृद्धि के साथ यूरोप ने शीत युद्ध के आखिर में दर्ज स्तर को भी पार कर लिया है। हेग में 76वां नाटो शिखर- सम्मेलन जिसमें रक्षा पर 5% खर्च का बड़ा लक्ष्य रखा गया था, भी, इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है, जिसमें 23 से ज्यादा देश पहले से निर्धारित 2% की सीमा को छू चुके हैं।

यूरोप अब कीव को सैन्य मदद का मुख्य आपूर्तिकर्ता है और यूक्रेन को ज्यादातर सैन्य हार्डवेयर यूरोप के रक्षा खरीद से भेजा जा रहा है, हालांकि हंगरी जैसे कुछ देश यूक्रेन का समर्थन करने में अधिक उत्साहित नहीं रहे हैं। ब्रुसेल्स में यह बात तेजी से समझ आ रही है कि यूरोपीय संघ को अपने परंपरागत आर्थिक गुट से आगे बढ़कर एक रणनीतिक कर्ता बनना होगा।

यह बात यूरोपीय संघ के भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर हाल ही में दिख रही है। यूरोप में लोगों की राय बहुत हद तक इस बदलाव का समर्थन करती है, जैसा कि कई सर्वेक्षणों में देखा गया है। फिर से शस्त्रीकरण होने से यूरोप को अमेरिका की बैसाखियों के बिना वैश्विक भू- राजनीति में एक स्वायत्त खिलाड़ी के रूप में उभरने का मौका मिलता है।

हालाँकि, यूरोपीय एकीकरण परियोजना और महाद्वीप में शांति एवं स्थिरता के बड़े मुद्दे को, शेष विश्व की शांति एवं स्थिरता से अलग या उसकी कीमत पर, अभी भी ठीक से विश्लेषण और संबोधित किया जाना बाकी है। हमने आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही अच्छा पैनल तैयार किया है जिसकी अध्यक्षता राजदूत गुरजीत सिंह कर रहे हैं। मैं एक विचारपूर्ण चर्चा की प्रतीक्षा में हूँ। पैनल के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं।

अज्ञात वक्ता: धन्यवाद मैडम। अब मैं राजदूत गुरजीत सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी आरंभिक टिप्पणी दें और आज की कार्यवाही का संचालन करें।

गुरजीत सिंह: मैडम राजदूत नूतन महावर जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए और फिर इतने कम शब्दों में सभी मुख्य मुद्दों को शामिल करने के लिए। आज मैं अपने जाने- माने साथियों के साथ आकर बहुत खुश हूँ। मैंने यूरोप में दो बार काम किया है। मेरी सबसे अच्छी पोस्टिंग इटली में थी, जहाँ केवल काम होता था, कोई मस्ती नहीं हुआ करती थी। सच कहें तो इससे उलट स्थिति थी- केवल मस्ती थी, काम नहीं लेकिन भारत से साथ मजबूत रक्षा संबंध भी थे। और फिर जर्मनी, जहाँ रक्षा का कोई मुद्दा ही नहीं था। इसलिए ये सभी मुद्दे जो आज यूरोप की अवधारणा नोट में हैं, उन पर 2017 तक मेरे काम करने के वर्षों में चर्चा नहीं हुई थी। ये सारे मुद्दे बिल्कुल नए मुद्दे हैं।

मेरे ख्याल से, ज़रूरी यह था कि क्या हम एक बहुध्रुवीय विश्व में सामान्य रूप से यूरोप और विशेष रूप से जर्मनी एवं फ्रांस के साथ काम कर सकते हैं। यह हमारे लिए अधिक ज़रूरी था। रणनीतिक साझेदारी का उनके लिए हिंद- प्रशांत से अलग अर्थ था। आज जब उन्हें फिर से सेना तैयार करने के लिए कहा जा रहा है तो उन्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि उनके सशस्त्र बलों का आकार बहुत छोटा है, उनकी रक्षा उत्पादकता बहुत सीमित है और क्या वे ऐसे समय में, जिसमें यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो नीचे न आ रही हो तो एक तरह से ठप पड़ी हुई है, ऐसा कर सकते हैं?

यूरोप में कल्याणकारी कार्यों पर खर्च बहुत अधिक होता है और जिन कुछ देशों का आपने उल्लेख किया, उन सभी में पेंशन टालने के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने पर घरेलू बहस जारी है। तो एक तरफ आर्थिक चुनौतियां हैं और दूसरी तरफ वे चाहते हैं सुरक्षा खर्च में 5% की वृद्धि कर दी जाए। मेरे समय में, यूरोपीय

संघ एक आर्थिक रूप से कार्यात्मक संगठन था जो दूसरे देशों को बताया करता था कि उन्हें अपने मानवाधिकार कैसे संभालने हैं। आज वे न केवल सदस्यों तक आर्थिक मदद पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिए भी धन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह बदलाव हुआ है।

यह बात यहीं छोड़ देते हैं। अब मैं इस पेपर पर दिए क्रम के साथ आगे बढ़ता हूँ। मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा से अनुरोध करता हूँ। मुझे लगता है कि मुख्य उद्देश्य यूरोप के सैन्यीकरण पर नज़र डालना है और क्या यह केवल यूक्रेन संकट के मामले में है या इसका कोई भावनात्मक संबंध भी है? वे कौन से विशेष क्षेत्र हैं जिन पर यह काम करता है? क्या यह केवल रूस के जवाब में है या और भी चुनौतियाँ होंगी जिन्हें यूरोप सेना बनने के बाद लेने को तैयार होगा? इस पेपर में कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल है जिन्हें आप पूछ सकते हैं। सर, 10 मिनट, धन्यवाद।

संजय वर्मा: बहुत- बहुत धन्यवाद सर। देवियों और सज्जनों नमस्कार। यहाँ आकर और इतने बड़े आयोजन के बीच मंच पर, अध्यक्ष महोदय और दर्शकों के बीच आकर मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह आपने यदि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उसमें भारत- यूरोप, समझौता, एफटीए (FTA) के बारे में बताया गया था, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। इसके साथ ही जबकि हम काफी समय से एफटीए के बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में भारत- यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा समझौता पर भी विचार कर रहे हैं। और जैसा कि राजदूत सर ने अभी कहा, बिल्कुल सही, हमारे बीतते हुए वर्षों में, चार दशक पहले और उसके बाद, यहाँ तक कि एक या दो दशक पहले की बात करें तो कभी भी ऐसे संबंध की ओर नहीं देखा गया जो भारतीय सेना के नज़रिए से सैन्यीकरण को देखता हो।

लेकिन यह कहने के बाद मैं वही शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ जो राजदूत सर ने किया, पुनः- सैन्यीकरण। यह अवसर, जिसे यूरोपीय संघ देख रहा है, मेरे ख्याल से, इससे बेहतर समय पर नहीं मिल सकता था, जहाँ हम आज हैं क्योंकि मैं आत्मनिर्भर भारत की हमारी अपनी पहल के साथ बहुत ज्यादा मेल देखता हूँ।

जहाँ तक पुनः- सैन्यीकरण की इच्छा की बात है, तो दोनों में बहुत कुछ एक जैसा है। वे यूक्रेन युद्ध और असल में, हथियारों के पूरी तरह से खत्म हो जाने की वजह से पैदा हुए खालीपन से प्रेरित हैं। सच कहें

तो, सभी कंपनियां, की जाने वाली सभी रक्षा आपूर्तियां, उनके ऑर्डर बुक पहले से ही भरे हुए हैं और उनके पास क्षमता नहीं है। उस कमी को तत्काल पूरा किया जा सकता है। मैं इस बारे में भी बात करूँगा।

लेकिन देखते हैं, आज की तारीख में, यदि आप बात कर रहे हैं– आप सबने रिज़ीलिअन्स 2030 पढ़ा होगा, उनकी योजनाएं, बजट का निर्धारित किया जाना जिसके बारे में आपने कहा, 5% खर्च, है ना - मेरे कहने का अर्थ है, जो देश हैं, वे यह पक्का कर रहे हैं कि जो खर्च पहले सामाजिक क्षेत्र पर किया जाता था अब उसे जबरदस्ती रक्षा क्षेत्र में किया जाएगा। यह एक कानून है, जो हमारे बजट में पहले ही हो चुका है, जिसमें हम कहते हैं कि भारतीय रक्षा पूंजी बजट का 60% से 70% देशी उत्पाद खरीदने पर खर्च किया जाएगा।

मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही हुआ है कि 2024 यूरोपीय रक्षा औद्योगिक रणनीति का प्रस्ताव है कि 2030 की कम- से- कम आधी रक्षा खरीद यूरोपीय रक्षा तकनीक एवं औद्योगिक बेस, ईटीआईडीबीपी (ETIDBP) से हो। उन्होंने कहा है कि यह कानून है। यहीं पर मैं कुछ समानताएं बता रहा था। अब, आय यूरोपीय सैन्यीकरण की प्रवृत्ति क्या है? इसकी कुछ विशेषताएं हैं, पहली, बहुत सारा पैसा लगाना। हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। यह एक नीति रूपरेखा के साथ आती है, बहुत ही सोची- समझी, तैयारी (रेडीनेस) 2030 या यूरोप का पुनर्शस्त्रीकरण (रीआर्म यूरोप), जो स्पष्ट रूप से बताता है, वास्तव में, यह एक प्रकार का आदेश है, यह एक ऐसी रूपरेखा प्रदान करता है जो बताता है कि हर एक सदस्य राष्ट्र को क्या करना चाहिए। इसलिए इस पर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है।

हथियारों का ज़खीरा खत्म होने के साथ, यूरोपीय देशों को पहले से ही संकट प्रबंधन हेतु तैयार रहने के तरीके से इतर यूक्रेन से संकट में पड़ी अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की सुरक्षा पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है, जो वहाँ हो रहा है। अब आपके प्रदेशों की स्वतंत्रता पर ज़ोर है। अब ध्यान गोला- बारूद, मिसाइल रक्षा, वायु रक्षा सहयोग प्रणाली, पुराने प्लेटफॉर्म्स को बदलने पर है जो वहाँ काफी समय से हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प बात है जो मुझे लगता है कि हमारे सामने भी आती है और वह है अमेरिका पर निर्भरता को कम करना, यह मौलिक कथन है।

तो यूरोपीय संघ के देशों के बीच एक मजबूत एकीकरण और सहयोग की आवश्यकता है। यदि ऐसा है तो भारत को कौन से अवसर मिल सकते हैं? इससे पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कुछ रुकावटें भी हैं जैसे यूरोपीय संघ की योजनाएं या तो गैर- यूरोपीय संघ ठेकेदारों को बाहर कर देती हैं या यूरोपीय संघ के संस्थानों की आवश्यकता होती है। हमें इसका प्रबंध करना होगा। इसके प्रबंधन का तरीका भी सरल है, मैं उस पर तब बात करूँगा जब मैं बताऊंगा कि भारत के लिए कौन से अवसर उपलब्ध हैं। वास्तव में, यही कानून या यही रुकावटें, जो कहती हैं कि यह गैर- यूरोपीय संघ ठेकेदारों को बाहर करती है या यूरोपीय संघ के संस्थानों की आवश्यकता है, एक अवसर के रूप में मिलती है।

फिर, यूरोपीय संघ के देश कुछ गैर- अमेरिकी साधनों में विविधता लाएंगे, शायद लागत के लिए, शायद अपनी आपूर्तिश्रृंखला में विविधता लाने के लिए। वे इसमें विविधता लाना चाहते हैं। तो अवसर क्या हैं? अवसर वे तकनीक हैं जिन पर आपकी नज़र है, शायद ड्रोन, बिना पायलट वाली प्रणालियां, एआई से चलने वाले कमांड और कंट्रोल डिसिज़न सपोर्ट सिस्टम्स, काउंटर ड्रोन और एकीकृत वायु रक्षा, संचार एवं अंतरिक्ष आधारित समाधान, लंबी दूरी के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने वाले हथियार, गोला- बारूद। इन्वेंट्री की आवश्यकता पूर्ववत है।

यहाँ टीयर 2 और टीयर 3 के प्लेयर्स के लिए अवसर हैं, जो हमारे देश में बहुत मजबूत स्थिति में हैं। इसलिए, यह हमें संयुक्त उपक्रम का मौका देता है। यूरोपीय संघ की सहायक कंपनियां, एसएएबी (Saab), पहले ही अपने जड़ें मजबूत कर चुकी हैं। यह उनमें से एक है और अभी ऐसी कई कंपनियां आने वाली हैं।

भारतीय एयरोस्पेस प्रोग्राम में सैफ्रन जिस तरह से काम कर रहा है, उस पर नज़र डालिए। ऐसी कई पहलें आने वाले समय में शुरू की जाएंगी। और केवल आपकी जानकारी के लिए, जैसा कि राजदूत सर ने भी कहा, एक समय, हम इस बारे में कभी बात ही नहीं करते थे। बीते आठ, नौ महीनों में, मैं तीन अलग-अलग देशों में था, जिसमें इटली और जर्मनी भी थे, संबंधों को बेहतर बनाने और भविष्य में आगे बढ़ने के नज़रिए के साथ। दो बातें हैं- पहली, टीयर 2, टीयर 3 की आपूर्ती श्रृंखला का एकीकरण। दूसरी, संयुक्त उपक्रम और यूरोपीय संघ- आधारित सहयोग। तीसरी बात, सहयोगी शोध एवं विकास कार्य या उभरती हुई तकनीकें। क्यों? क्योंकि आज सभी उभरती हुई प्रौद्योगिकियां दोहरे- उपयोग की तकनीकें हैं।

इसमें एक अवसर है क्योंकि कुछ यूरोपीय देश रक्षा से जुड़े मामलों को साझा करने में संकोच कर रहे हैं। वास्तव में, जर्मनी की मेरी हाल की यात्रा से पता चला कि उनके लिए रक्षा के क्षेत्र में किसी भी तरह के सहयोग को कर पाना बहुत सरल नहीं होगा। इसलिए अंतरिक्ष, संचार, सामग्रियों, उन्नत सामग्रियों, ऊर्जा, ये सभी क्षेत्र हमारे लिए संयुक्त उपक्रम हेतु आसानी से उपलब्ध हैं। आत्मनिर्भर भारत और भारतीय रक्षा खरीद में जिस प्रकार से नीतिगत परिवर्तन हुए हैं, उसे चार वर्षों तक, लगभग सात, आठ साल पहले, मैंने देखा है, बीते 8 से 10 वर्षों में जो हुआ है उसमें जबरदस्त परिवर्तन दिख रहा है।

मुझे लगता है कि हमें बहुत ध्यान से संवाद करना चाहिए और इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल और समय के हिसाब से अपने विचार आप सबके साथ फिर से साझा करूँगा। धन्यवाद।

गुरजीत सिंह: बहुत- बहुत धन्यवाद। बहुत ही अनुशासित, सटीक और अच्छी बातें। इनकी प्रस्तुति ने मेरे मन में एक सवाल पैदा किया कि क्या भारतीय कंपनियां इन तकनीकों में शामिल जर्मनी या यूरोप में कंपनियों को खरीद सकती हैं? नागरिक क्षेत्र में बहुत कुछ है। जब मैं राजदूत था, तो मैं जर्मनी के लोगों से कहता रहता था कि 2005 से 2015 के दशक में जर्मनी में वास्तव में भारतीय निवेश बहुत अधिक हुआ है, जबकि जर्मनी में इसका उल्टा हुआ है। बिग फोर में से एक की रिपोर्ट के अनुसार हमने इसे साबित भी किया है, जो सच है। भारतीय कंपनियां वहाँ की कंपनियों, टेक्नोलॉजी कंपनियों को खरीद रही थीं।

अब चीन में, थोड़ी शंका है। भारत, कोई शंका नहीं। मुझे लगता है कि हमें इसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे मकसद क्या हैं, और हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका बहुत- बहुत धन्यवाद। मुझे अपनी प्यारी दोस्त प्रोफेसर उम्मू सलमा बावा को आमंत्रित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि वह अब हमें उस बारे में और जानकारी देंगी जिसके बारे में जनरल वर्मा ने पहले ही बहुत अच्छी तरह से बताया था। अब आपकी बारी मैम। आपके पास भी 10 मिनट का समय होगा।

उम्मू सलमा बावा: बहुत- बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। राजदूत नूतन महावर जी नमस्कार, और आज का यह अवसर प्रदान करने के लिए आईसीडब्ल्यूए का भी धन्यवाद। इस विषय पर चर्चा करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। यूरोप का पुनर्शस्त्रीकरण (रीआर्म यूरोप/ReArm Europe) इसी वर्ष शुरू हुआ था। लेकिन मैं समय में थोड़ा पीछे चलती हूँ और बताती हूँ कि आने वाले 10 मिनटों में आप सब के साथ क्या साझा करूँगी। पहला, पृष्ठभूमि का पता लगाना। दूसरा, यूरोप का पुनर्शस्त्रीकरण क्या है? चलिए फिर उसी पर नज़र डालते हैं, और फिर संभावनाओं एवं चुनौतियों पर बात करेंगे।

मुझे लगता है कि यह बताना ज़रूरी है कि 2024 में, यूरोपीय रक्षा उद्योग रणनीति मार्च के महीने में जारी की गई थी। और इसकी पृष्ठभूमि में, निश्चित रूप से, यूक्रेन में जारी युद्ध है। तो सुरक्षा के नज़रिए से एक बुनियादी सवाल यह है कि 24 फरवरी 2022 की घटना ने, जिसे राजदूत मैडम ने एक सोया हुआ दानव कहा था, उसे कैसे जगाकर कहीं अधिक सैन्य भूमिका निभाने वाला बना दिया? मुझे लगता है कि यूरोप में सुरक्षा काफी लंबे समय से इंसानों की सुरक्षा के नज़रिए से देखा जाता रहा है।

आर्थिक संपन्नता ने जीवन- स्तर को बेहतर बनाना, लाभ पहुँचाए, पूरी रेंज को कवर किया और यूरोपीय संघ को इतना आकर्षक बनाया कि 1992 में, यूरोपीय संघ के बनने और शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद, मध्य और पूर्वी यूरोप के देशों ने उन दो ज़रूरी संस्थानों में शामिल होने के लिए बड़ा कदम उठाया जो आर्थिक सुरक्षा और सैन्य दृष्टि से भी सुरक्षा की गारंटी देते थे।

लेकिन 20 साल बाद की घटनाएं कुछ और ही इशारा कर रही थीं। केवल आर्थिक सुरक्षा का होना ही काफ़ी नहीं था। यदि क्रीमिया चेतावनी नहीं था तो 2022 पक्की चेतावनी थी। पिछले तीन वर्षों में अंतरराष्ट्रीय प्रयासों और उससे भी ज्यादा ज़रूरी वॉशिंगटन की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप के अपने चुनावी एजेंडे में यह कहने के बावजूद की वह तत्काल शांति समझौता करने का प्रयास करेंगे, जो उनकी पहली प्राथमिकता थी, घटनाएं लिखी हुई स्क्रिप्ट जैसी नहीं हो पाईं। यह कोई रंगमंच नहीं है लेकिन सबसे बुरे किस्म का रंगमच बन गया है क्योंकि युद्ध जितना लंबा चलता है, शांति बहाल करने की कीमत उतनी ही अधिक होती है। मुझे लगता है कि यूरोप ने इसी का सामना किया है।

यूरोप को एक के बाद एक चेतावनियां मिली हैं, कोई भी इसे समझ सकता है, 2022 की शुरूआत में हुए रणनीतिक करार से, जो युद्ध आरंभ होने के ठीक बाद हुआ था, 2024 में औद्योगिक रक्षा पक्ष को आगे बढ़ाने तक और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि इस साल, पूरा पुनर्शस्त्रीकृत यूरोप आपको उन ज़रूरी कदमों की एक श्रृंखला दिखाता है जो यूरोपीय सुरक्षा कौन देगा, इस चुनौती को हल करने के लिए उठाए गए हैं। जैसा कि राजदूत मैडम ने बताया था, उत्कृष्ट उदाहरण नाटो द्वारा ऐसा किया जाना था। नाटो ने अपने 32 सदस्यों के साथ और यूरोपीय संघ अपने 27 सदस्यों के साथ इस पर आम देशों के मामले में स्पष्ट रूप से ओवरलैप देखता है।

लेकिन आज, मुझे लगता है कि 20 जनवरी 2025 को शायद अटलांटिक पार के संबंधों में विश्वास को बहुत बड़ा झटका लगा, यदि कभी कुछ लगा हो, और अटलांटिक पार को समझने का एक लंबा इतिहास रहा है क्योंकि आपसी संबंधों में विश्वास का जो कारक इतना आवश्यक है, उसे ऐसा झटका लगा जो कभी ठीक नहीं होगा। ट्रंप, 2.1 ने पहले ही संकेत दे दिया था कि यूरोपीय देश रक्षा के क्षेत्र में कम सक्रिए हैं और भुगतान भी कम कर रहे हैं, 2% की सीमा को पार किया जाना चाहिए। फिर 2022 से जो हुआ है, वह खर्च को और बढ़ाना है।

तो 5% का प्रस्ताव आगे किया गया और यदि आप पुनर्शस्त्रीकृत यूरोप को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि विचार यह है कि यूरोप को अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी स्वयं उठानी होगी, भले ही इस वर्ष की शुरूआत में एक सफल नाटो शिखरसम्मेलन ने सभी को भरोसा दिलाया था कि अनुच्छेद 5 उपलब्ध होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अटलांटिक पार के इतिहास में और 1949 में नाटो के बनने के बाद पहली बार, अनुच्छेद 5 का असर सामने आया है। कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि गलती कहाँ होगी और क्या वॉशिंगटन वास्तव में अपने साथियों के लिए कुछ करने को तैयार है।

मुझे लगता है कि इस मामले में, मैं आपका ध्यान उन पांच क्षेत्रों की ओर दिलाना चाहती हूँ जिन्हें पुनर्शस्त्रीकरण कार्यक्रम में पहचाना गया है, जो यूरोप को सुरक्षा देने की दिशा में एक और कदम है। उनमें से एक, बेशक, राष्ट्रीय राजधानी को उनके रक्षा खर्च को पूरा करने में मदद करना है। यह एक राजकोषीय साधन के बारे में है। दूसरी बात, यह रक्षा निवेश की एक नई योजना भी है। तीसरा, आयोग यूरोपीय संघ के अप्रयुक्त कोष का प्रयोग रक्षा संबंधी निवेश में करना चाहता है।

चौथा, यह रक्षा के मकसद के लिए निजी पूंजी भी लाना चाहता है। और आखिर में, यह यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक या ईआईबी (EIB) को भी इसमें शामिल करना चाहता है। स्पष्ट है, यदि पुनर्शस्त्रीकृत यूरोप में कोई एक चीज़ है, तो उन पांच बातों में जिन पर ज़ोर दिया गया है वह रक्षा में अधिक निवेश के बारे में है, ठीक है ना? लेकिन क्या रक्षा के क्षेत्र में अधिक निवेश करने से वास्तव में सुरक्षा प्रदान करने के लिए वैसी क्षमता और औद्योगिक तैयारी संभव है? यह मूल सवाल है।

और जैसा कि हमारे पास है–जनरल आप सुन रहे हैं ना, मंशा और कार्रवाई एवं सैनिकों की असल तैनाती में बहुत समय लगता है। इस देरी के दौरान, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। बहुत सी चीजें जो राजनीतिक रूप से, मुझे लगता है, बहुत ज़रूरी होने वाली हैं। और उनमें से एक यह होगी कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन शांति योजना पर ज़ोर देंगे, लेकिन फिर उस शांति योजना के लिए यूक्रेन को सुरक्षा कौन देगा जिसमें हम देखते हैं कि यूरोप कभी- कभी थोड़ा- बहुत शामिल है और कबी- कभी नहीं? यह बहुत ज़रूरी होने वाला है।

तो, समय का पूरा ख्याल रखते हुए और क्योंकि इसकी अध्यक्षता एक अच्छे पुराने मित्र कर रहे हैं और मैं नहीं चाहूँगी कि वे मुझे समय- सीमा की याद दिलाएँ, चलिए जल्दी से संभावनाओं और समस्याओं पर बात कर लेते हैं। मुझे लगता है कि यूरोपीय नज़रिए से अटलांटिक पार से जो कुछ भी आया है, उससे अलग रक्षा के क्षेत्र को वास्तव में सुलझाने के लिए पहली कोशिश है। पूरी तरह से यूरोपीय नज़रिए से, यह कहना अच्छा होगा कि पहली बार यूरोपीय असल में अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। यह कार्रवाई में कैसे बदलेगा?

अच्छा कदम तो यह होगा कि रक्षा क्षेत्र में खर्च बढ़ने का अर्थ यह भी होगा कि सदस्य देशों को पता चलेगा कि यूरोपीय स्तर पर उनके लिए बैकअप मौजूद है। यह बात उन देशों के लिए विशेष रूप से सच है जो निवेश नहीं कर पा रहे हैं, अपने कल्याणकारी उपायों, आर्थिक पहलुओं का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि बीते तीन वर्षों में यूरोप में ऊर्जा विविधिकरण हो रहा है, जिससे देशों पर लागत का बोझ बढ़ गया है, इसका मतलब है इससे उत्पादन की लागत बढ़ गई है।

दूसरा, पुनर्शस्त्रीकृत यूरोप की रणनीतिक स्वतंत्रता के विचार को और बढ़ाएगा, यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे प्राथमिकता दी गई है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे पूरा करना बहुत दूर की बात होगी लेकिन शायद यह पहला कदम होगा जिसमें अमेरिकी सेना से निर्भरता हटाकर एक स्वतंत्र यूरोपीय रक्षा क्षमता विकसित की जाएगी। तीसरा, मुझे लगता है कि पुनर्शस्त्रीकृत यूरोप उस क्षमता की कमी को भी पूरा करता है जिसका यूरोप हमेशा से सामना करता रहा है, और इसका यह मतलब होगा कि वायु और मिसाइल रक्षा, तोपखाना प्रणालियां, ड्रोन और सैन्य गतिशीलता के ज़रूरी आवश्यक क्षेत्रों की पहचान करना और सबसे ज़रूरी बात, हाइब्रिड युद्ध के मामले में, हम साइबर और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पर नज़र रख रहे हैं।

और चौथा सकारात्मक पक्ष यह होगा कि यह रणनीति साथ मिलकर काम करने के बेहतर तरीके को बढ़ावा देती है। इसमें, कोई भी देख सकता है कि चुनौती क्या है। इसका मतलब है कि मिलकर काम करने के लिए इसे बिखराव से उबरना होगा। मैं जल्दी से बता दूँ कि पुनर्शस्त्रीकृत यूरोप के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। पहली है- बिखराव की समस्या, कई देशों में इसे दोहराने की चुनौती, वित्तीय दबाव, और इनसे निपटते हुए घरेलू बहसों को प्रबंध करने की क्षमता।

तीसरा, यदि आप पुनर्शस्त्रीकृत प्रोग्राम की घोषणा भी करते हैं तो सच तो यह है कि बुनियादी ढांचे की कमी है और सभी देश किसी निजी को तत्काल औद्योगिक रक्षा क्षमता में नहीं बदल पाएंगे, जिसे तत्काल संवर्धित किया जा सके। चौथा, बेशक, खरीद का पूरा मुद्दा है। यूरोप, अपनी कई उद्योगों के साथ और जिसे राष्ट्रीय प्राथमिकता मोड कहा जाता है, उसके लिए तेज़ी से बढ़ाना और जिसे यूरोप-व्यापी निर्णयन कहा जाता है, उसे देना मुश्किल होगा, जहाँ इसका मतलब होगा कि सामूहिक हित के लिए किसी एक के राष्ट्रीय हित को छोड़ना होगा।

और हाँ, अटलांटिक पार का तनाव और भू- राजनीतिक माहौल का प्रबंध करना बहुत आवश्यक होने वाला है। यह देखना लाभकारी होगा कि जैसे- जैसे हम आगामी मार्च 2026 में आएंगे और युद्ध चौथे साल में पहुँचेगा, दो साल तक लगातार औद्योगिक रक्षा रणनीति और पुनर्शस्त्रीकृत यूरोप की लॉन्चिंग होगी, क्या इससे यूरोपीय महाद्वीप पर वास्तविक परिनियोजन, वास्तविक क्षमता बढ़ाने और यूरोप जिसे दुश्मन मानता है, उसका सामना करने के लिए असल तैयारी के मामले में कुछ सकारात्मक प्रभाव होगा? दीर्घकाल में, पुनर्शस्त्रीकृत यूरोप और जो भी चुनौतियाँ आएंगी, उन्हें यह भी देखना होगा कि यूरोप को अपनी जटिल

भौगोलिक स्थिति से निकलने का रास्ता तलाशना होगा क्योंकि भौगोलिक स्थिति ही हर किसी की किस्मत का निर्धारण करती है। धन्यवाद।

गुरजीत सिंह: धन्यवाद प्रोफेसर सलमा बावा। हम जिस अवधारणा पर आज चर्चा कर रहे हैं उसकी बहुत ही सटीक परिभाषा और आपके विचार से उनकी क्या स्थिति होगी, आपने यह भी बहुत स्पष्ट रूप से हमें बताया। आपकी प्रस्तुति से मेरे मन में कुछ सवाल पैदा हुआ है। क्या ब्रेक्सिट ने यूरोप की रक्षा संगठन का प्रभाव कम कर दिया है? क्योंकि पहले जो ब्रिटिश थे, उनके साथ ब्रिटिश, फ्रेंच और जर्मन मिलकर डिफेंस समन्वय करते थे, लेकिन अब ब्रिटिश नहीं हैं।

दूसरा, जर्मनी के जैसे, रक्षा पर बढ़ा हुआ खर्च सबसे पहले अमेरिकी हथियार खरीदने में जाता है। तो यह अटलांटिक पार के देशों के लिए तोहफे जैसा है। तीसरा यह है कि 5% में से 1.5% असल में उससे जुड़ी अवसंरचनाओँ के लिए है। अब मुझे लगता है कि यह बहुत ज़रूरी है और इसमें हमारी भी भूमिका है, जो गैर- रक्षा, गैर- घातक है, लेकिन तकनीक के क्षेत्र में आप बहुत कुछ कर सकेत हैं।

और आपने बताया कि कंपनियों को यूरोपीयकृत करने की आवश्यकता है। सभी भारतीय तकनीकी कंपनियां यूरोपीयकृत हैं। तो हमें यह लाभ पहले से ही ज़मीन पर मिल रहा है। मुझे अब डॉ. एलेक्सेई ज़खारोव को आमंत्रित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। डॉ. ज़खारोव ओआरएफ के स्ट्रैटेज़िक स्टडीज़ प्रोग्राम के फेलो हैं और मुझे बताया गया है कि वे रूस से हैं। अब हमारा नज़रिया थोड़ा अलग होना चाहिए। सर, आपके पास अपने विचार साझा करने के लिए 10 मिनटों का समय है, धन्यवाद।

एलेक्सेई ज़खारोव: राजदूत महोदय, धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आईसीडब्ल्यूए को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पैनल में इतने जाने- माने विशेषज्ञों के बीच होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मुझे लगता है कि चर्चा का विषय वाकई गंभीर और ज़रूरी है और बिल्कुल सही समय पर लिया गया है। मैं यूरोपीय पुनर्शस्त्रीकरण के बारे में रूस के नज़रिए के बारे में बात करूँगा। मुझे लगता है कि यदि हम संघटन/ लामबंदी (मोबिलाइज़ेशन) शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात पर ज़ोर देना होगा कि ये यूरोपीय सैन्यीकरण के शुरुआती दिन हैं क्योंकि पूर्ण बोध से मुझे लगता है कि सैन्यीकरण हेतु अलग-अलग क्षेत्र में दखल देने की आवश्यकता है।

यदि हम यूरोप की राजनीतिक बहसों या सामाजिक जीवन को देखें तो मुझे लगता है कि हमें वहां संघटन/ लामबंदी (मोबिलाइज़ेशन) के कोई संकेत नहीं मिलेंग, विशेषरूप से यदि हम फ्रांस जैसी कुछ यूरोपीय राजधानियों में हाल की बहसों को ध्यान में रखें, जहाँ रूस के संकट के बारे में अलग- अलग राय है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल फैबियन मैंडन की हाल की बातों का जवाब भी शामिल है। इसलिए मुझे लगता है कि यह एक साफ़ उदाहरण है कि यूरोप को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इस पर अलग- अलग राय हैं और यह शायद बस एक शुरुआत है, यह संघटन का बस एक शुरुआती चरण है।

मेरा दूसरा प्वाइंट यूरोप और रूस दोनों से आर रही बातों के बारे में है। मुझे लगता है कि कभी- कभी वे अलग- अलग प्रकार की होती हैं क्योंकि यदि हम यूरोप के अलग- अलग नेताओं के बयान देखें तो उनमें से कुछ कह रहे हैं कि रूस एक कागज़ी शेर है और वह यूक्रेन में जंग हार रहा है और उसका राजनीतिक शासन अस्थिर है। यदि हम दूसरे बयानों पर गौर करें तो वे एक प्रकार से रूस की धमकियों को बढ़ा- चढ़ाकर बताने की कोशिश कर रहा है, यह कहते हुए कि रूस के साथ युद्ध होने वाला है और 2029 या 2030 के लिए कुछ भविष्यवाणियां भी कर रहे हैं।

रूस में भी हालात ऐसे ही हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आम तौर पर यूरोप और विशेष रूप से यूरोपीय संघ को एक ऐसा संगठन माना जाता है जो एक साथ नहीं रहता, अलग- अलग देशों के बीच बहुत सारी कमियां हैं और सैन्य खर्च बढ़ाने की वर्तमान कोशिशों का असर राजनीतिक प्रणाली और उनकी अर्थव्यवस्था पर ज़रूर पड़ेगा, जिससे सत्ता में बदलाव होगा और दूसरी राजनीतिक शक्तियां सामने आएंगी जो रूस के लिए फायदेमंद हो सकती हैं।

मुझे लगता है कि यदि हम और गंभीरता से विश्लेषण करें तो शायद हम देख पाएंगे कि यूरोप और रूस के बीच अभी जो स्थिति है, जहाँ प्रत्यक्ष सैन्य जंग की उम्मीद लगभग जरूरी हो गई है, यदि हम बयानों को सुनें, तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा बढ़ा- चढ़ाकर कहा गया है। यदि हम विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि असल में यूरोपीय पुनर्शस्त्रीकरण अभी, फिर से, हम पांच से सात साल या दीर्घ काल के नज़रिए की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी यह रूस की सुरक्षा के लिए कम ख़तरा है, बल्कि रक्षा क्षमताओं को बेहतर करने की कोशिश अधिक है और शायद रूस के लामबंदी का ही जवाब है।

मुझे लगता है कि यूरोपीय सदस्य देशों के दो मुख्य मकसद हैं। पहला, किसी देश, खासकर बाल्टिक देशों में रूस के हमले के खिलाफ सुरक्षा को बढ़ाना। यह सीमा पर रक्षा सुदृढ़ करने की अलग- अलग कोशिशों से नज़र आता है जैसे टैंक- रोधी खाईयां, ड्रैगन टीथ और बारूदी- सुरगें बनाने जैसे दूसरे उपाय।

दूसरा, भविष्य के लिए सैन्य क्षमताओं में ज्यादा समानता पक्का करना, क्योंकि मुझे लगता है कि रूसी और यूरोपीय, दोनों के सैन्य विशेषज्ञों को लगता है कि उनकी वर्तमान सुरक्षा क्षमताओँ में कुछ कमियां जरूर हैं जिन्हें दुरुस्त करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल वर्मा ने पहले ही उन सिस्टम के बारे में बताया है जिन्हें यूरोपियन अब ढूंढ़ रहे हैं, खासकर उन्हें गोले के उत्पादन की कमी का एहसास है और हाल ही में जर्मन कंपनियों द्वारा नए संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। उनका मंशा अच्छी है लेकिन मेरे ख्याल से यदि हम आउटपुट संख्या को देखें तो हम पाएंगे कि वे एक गंभीर, गहन सैन्य युद्ध को बनाए रखने के लिए काफी नहीं हैं।

विशेषरूप से इस क्षेत्र में, रूस ने बीते तीन वर्षों में अपने गोले और गोलियों के उत्पादन को बहुत बढ़ा दिया है। यही बात ड्रोन सिस्टम और काउंटर- ड्रोन सिस्टम्स पर भी लागू होती है। मुझे लगता है कि न केवल उत्पादन पर बल्कि इस क्षेत्र में प्रशिक्षण कौशल और तकनीकों पर भी फोकस की कमी है, जैसा कि यूक्रेन में जारी युद्ध से पता चलता है, ड्रोन्स की संख्या से कहीं ज्यादा जरूरी मुद्दा है।

साथ ही, यदि हम अपने सैन्य संतुलन की तुलना करें तो यूरोप कई मामलों में भी आगे हैं, जैसे यदि हम फाइटर जेट्स की संख्या की तुलना करें या नई पीढ़ी के फाइटर जेट्स में उनके बदलाव की। या यदि हम समुद्री क्षेत्र की बात करें तो समुद्र क्षेत्र में खासकर सतही पोतों के मामले में, मेरे ख्याल से यूरोप को उत्कृष्टता से लाभ होता है।

अगली बात यह है कि रूस, अमेरिका की काबिलियत को ध्यान में रखे बिना यूरोप के संकट को नहीं समझता। मुझे लगता है कि ट्रंप प्रशासन के अब तक के अस्थिरता के कारण और अटलांटिक पार संबंधों में कई मुश्किलों के बावजूद यह माना जाता है कि अमेरिका अभी भी सैन्य क्षेत्र समेत अपनी नाटो की

ज़िम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध है। इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम में हो रहे विकास पर रूस के जवाब, यदि हम इसे ऐसे कहें, मेरे विचार से उनका मकसद यूरोप को नहीं बल्कि अमेरिका को संकेत देना है। मैं रूस के हाल ही में किए गए नए हथियारों के परीक्षण पर ज़ोर देना चाहूँगा, जैसे कि ब्यूरेवेस्टनिक मिसाइल या पोसाइडन, परमाणु शक्ति संपन्न पनडुब्बियां और दूसरी अनेक प्रणालियां। मुझे लगता है कि यह केवल यूरोप के बारे में नहीं है और यह यूरोप के बारे में उतना नहीं है जितना अमेरिका- रूस के संबंध में गतिकी के बारे में है। यहाँ रूस नाटो को एक पूर्ण संस्था के तौर पर देख रहा है, नाटो के यूरोपीय अंश को बड़े गुट से अलग नहीं कर रहा है।

आखिरी बात यह है कि रूस और यूरोप के बीत किसी भी प्रत्यक्ष युद्ध की उम्मीद अभी दूर की कौड़ी है, फिर भी मुझे लगता है कि अभी भी कुछ ऐसे हालात हैं जहाँ हम बदकिस्मती से दोनों तरफ से कोई बड़ी घटना देख सकते हैं। मेरे ख्याल से तो दो बड़े जोखिम या संकट वाले क्षेत्र हैं। पहला है- यदि वर्तमान शांति प्रयासों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकता है तो यूक्रेन में युद्ध जारी रहेगा। यदि यूक्रेन में किसी भी यूरोपीय सैनिक को तैनात करने की योजना सच हो जाती है तो बेशक हम रूस और कुछ यूरोपीय सदस्यों या पूरे नाटो के बीच सीधे युद्ध की संभावना को सच होता देख सकते हैं।

और चिंता का दूसरा क्षेत्र है बाल्टिक सागर। जहाँ असल में अब तनाव बहुत बढ़ गया है, तनाव वाले क्षेत्रों में व्यापार क्षेत्र भी है और रूस को अपने तेल टैंकरों की पहरेदारी करने के लिए नौसेना के जहाज़ भेजने पड़ रहे हैं। मैं कहूँगा कि मैं इस क्षेत्र को भविष्य की किसी भी वार्ता के लिए चिंता के एक और क्षेत्र के रूप में देखूंगा और इसी के साथ अपनी बात को खत्म करूँगा। मेरे विचारों को ध्यान से सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।

गुरजीत सिंह: मुझे आपके विचारों को सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि ये ऐसी बातें नहीं हैं जो हम आमतौर पर भारत में सुनते हैं। इसलिए बहुत अच्छा लगा लेकिन मुझे आशा है कि आपने आखिर में जो कहा, कि और भी युद्ध हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह सच न हो। मुझे लगता है कि सच में रूस द्वारा इस युद्ध को समाप्त कर दिए जाने की जरूरत है और एक बहुध्रुवीय विश्व में एक बड़े ध्रुव के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी उचित जगह लेने की भी आवश्यकता है। यूक्रेन में बिना नतीजे के युद्ध की वजह से, बहुध्रीवीय विश्व में रूस की भूमिका निभाने की क्षमता कम हो गई है। हिंद- प्रशांत से

गैरमौजूदगी, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से गैरमौजूदगी, जी20 शिखर सम्मेलन से गैरमौजूदगी, यह सब बताता है।

मुझे रूस वापस चाहिए और उसके लिए आपको यूक्रेन में युद्ध समाप्त करना होगा और हमें आशा है कि आप अभी जो भी कर रहे हैं, वह होगा। लेकिन फिर से, आपकी बातों से मेरे मन में कुछ सवाल उठे और यह वही बात है जो आपने कही थी। यदि यूरोप की कंपनियाँ रक्षा, सैन्य, औद्योगिक परिसर में प्रवेश करना शुरू कर देंगी तो वे फिर से आत्मसात हो जाएंगी। यूरोपीय कंपनियों को भारत के बारे में विचार करने हेतु बाहर लाना इतना मुश्किल है कि ऐसा कर पाना बहुत कठिन हो जाएगा। वे फिर से अपने भीतर झांकना शुरू कर देंगी और कहेंगी, यूरोप में हमारा बाज़ार बहुत बड़ा है, हम भारत जाकर क्यों जाएं? एक समस्या यह है।

दूसरी समस्या है जिसे मैंने कुछ महीने पहले पांच नार्डिक देशों में अपनी आँखों से देखा था। मैंने पाया कि सरकारों के स्तर पर, हर कोई इस नाटो 5% से खुश था लेकिन यदि आप लोगों से बात करें, तो वे खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसमें आगे बढ़ रही है और अब वे हमसे कहेंगे कि हम आपके लिए चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यों में कटौती करेंगे, जिसके लिए हम तैयार नहीं है। कम में समझें, क्या मैं यूक्रेन की मदद के लिए अपनी पेंशन कम करने जा रहा हूँ? असल में बात यहीं आकर खत्म हो जाती है और जवाब था नहीं।

मुझे लगता है कि यूरोप के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे अपने लोगों को कैसे यकीन दिलाएं कि वे जो कर रहे हैं वह सही है। दूसरी बात यह थी कि हम यूरोपीय एकीकरण की बात करके हैं लेकिन एस्टोनिया में मैंने यूरो या डॉलर कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता था। उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था। क्यों? जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा कि वह देश भौगोलिक रूप से रूस के बहुत करीब है। तो रूस के जितने पास होंगे आपके कार्ड्स काम नहीं करेंगे। मैंने तो यही सीखा। और मज़ेदार बात यह थी कि मुझे अपने लंच के बिल का भुगतान करना था इसलिए मैं ने 50 यूरो का नोट निकाला। उस लड़की ने कभी भी 50 यूरो का नोट नहीं देखा था। मैंने कहा कि तुम यूरो मुद्रा वाले देश में रहती हो। उसने मुझसे कहा, कृपया मुझे 10 यूरो दें। मेरे पास 10 यूरो नहीं थे।

इन देशों के बीच इस लड़ाई की वजह से बहुत सारी व्यावहारिक मुश्किलें आ रही हैं और यह तथाकथित यूरोपीय एकीकरण ज़मीन पर नहीं है। पूर्वी यूरोपीय, बाल्टिक देश असल में अभी भी वहीं हैं जहाँ वे थे, रूस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। बस यही एक फर्क है। वे यूरोप में कैसे शामिल हुए हैं, मुझे लगता है कि इस बारे में सवाल पूछे जाने चाहिए।

मुझे लगता है कि हमारे पास बहुत सारे शानदार वक्ता हैं। अब मैं प्रश्नोत्तर सत्र की शुरूआत करता हूँ। हमारे पास केवल दस मिनटों का समय रह गया है, इसलिए केवल पांच प्रश्न या टिप्पणियां। कृपया प्रश्न और टिप्पणियों को संक्षिप्त रखें और फिर हम उत्तरों का अंतिम दौर शुरू करेंगे। मैं निश्चित रूप से महिलाओं को प्राथमिकता देना चाहूँगा। धन्यवाद।

हिमांशी मावी: नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी मावी है, मैं टीआईईएस (TIES) जो एक विचारक समूह अनुसंधान संगठन और मीडिया प्लेटफॉर्म है, की युवा प्रतिनिधि हूँ। एक युवा प्रतिनिधि होने के नाते, मुझे मुख्य रूप से सेना के वापस जाने संबंधी चिंता के बारे में जानकारी है। क्योंकि यूरोप अभी फिर से हथियार उठाने की ज़रूरत का सामना कर रहा है इसलिए मेरा सवाल पूरे पैनल के लिए है, क्योंकि यह रणनीति, राजनीति और संचार से जुड़ा है।

सेना के विश्षेज्ञों के लिए, मेरा सवाल यह है कि अपराध से निवारण में फर्क करने के लिए आख्यान में किन विशेष उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए? मैं अपना प्रश्न दोहराना चाहूँगी। अपराध से मुक्ति के आख्यान में किन विशेष उद्देश्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए? और राजनीतिक एवं यूरोपीय अध्ययन के विशेषज्ञों के लिए, ससंजक क्या है?

गुरजीत सिंह: एक सवाल। अच्छी बात है। धन्यवाद। कोई और है दो सवाल पूछना चाहता है? जी हाँ। इनके बाद कौन सवाल पूछने जा रहा है? अच्छी बात है, वहाँ बैठी महिला। कृपया उन्हें माइक दें। इनके बाद उस सज्जन को माइक दिया जाए।

दीपक कुमार शर्मा: पैनल के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक कुमार शर्मा है। मैं टीआईईएस (TIES) में रिसर्च एसोसिएट हूँ। मेरा सवाल यूरोपीय संघ के अंदरूनी हिस्सों के बारे में है। पुनर्शस्त्रीकरण

एजेंडे में, पूरे यूरोपीय संघ के लिए एक ड्रोन शील्ड का भी उल्लेख किया गया था। लेकिन फ्रांस और जर्मनी जैसे कई बड़े प्लेयर्स इस बारे में बहुत संरचनात्मक थे। वे इसे लेकर संरचनात्मक थे क्योंकि वे इसे खुद स्वतंत्र रूप से संभालना चाहते थे और उस ड्रोन शील्ड के लिए ब्रुसेल्स पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे।

और इसी तरह, भविष्य का लड़ाकू विमान सिस्टम जैसे छठी पीढ़ी का विमान पहले ही खत्म हो चुका है और साझेदारी काम नहीं कर रही है क्योंकि उस स्थिति में विकास साझेदार को लेकर मतभेद थे, है ना? तो जब पूरे यूरोप को फिर से हथियारबंद करने की बात आती है तो आप इन अंदरूनी मतभेदों को कैसे सुलझाएंगे?

गुरजीत सिंह: एक सवाल। जी मैडम। माइक यहाँ है। जी हाँ। कृपया अपने पीछे माइक बढ़ाएं।

अज्ञात प्रतिभागी: नमस्कार। मैं टीआईईएस (TIES) से एक और युवा प्रतिनिधि। मेरा नाम सुमेरा है।

गुरजीत सिंह: क्या यहाँ कोई ऐसा भी है जो इस संस्थान से न हो?

अज्ञात प्रतिभागी: टीआईईएस (TIES) एक छात्र संगठन है, लेकिन यहाँ के छात्र दिल्ली के अलग- अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से हैं।

गुरजीत सिंह: अच्छा, अच्छी बात है। कृपया अपनी बात जारी रखें। धन्यवाद।

अज्ञात प्रतिभागी: मेरा सवाल यह है कि- क्या यूरोप अपनी तकनीक एवं रणनीति के लिए अमेरिका पर बहुत ज्यादा निर्भर हुए बिना अपनी रक्षा प्रणाली को वाकई आधुनिक बना सकता है?

गुरजीत सिंह: इतना संक्षिप्त प्रश्न पूछने के लिए बहुत धन्यवाद। जी हाँ, क्या आप भी टीआईईएस (TIES) से हैं?

अज्ञात प्रतिभागी: जी नहीं, मेरा नाम समीर है और मेरा सवाल है- क्या ब्रुसेल्स प्रतीक्षा करेगा और इस योजना पर धीरे- धीरे कदम बढ़ाएगा, इस उम्मीद के साथ कि ह्वाइट हाउस में, मान लें कि आने वाले कुछ वर्षों में कोई नया चेहरा आ जाएगा? तब तक, यह विश्वास दिलाएगा कि ठीक है, हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ज़मीन पर कुछ भी रचनात्मक नहीं करेंगे।

गुरजीत सिंह: धन्यवाद। इनके ठीक पीछे, जी हाँ। माफ करें, वो और फिर हम सवालों का जवाब देना शुरू करेंगे।

अज्ञात प्रतिभागी: सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, रक्षा तकनीक के संदर्भ में, आज हम चीन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं?

गुरजीत सिंह: जी हाँ, यहाँ, नहीं आपके पीछे। अपने पीछे वाले व्यक्ति को दें।

अज्ञात प्रतिभागी: धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा, हम यूरोप को फिर से हथियारबंद करने की बात कर रहे हैं लेकिन इस शब्द का विरोध हुआ और फिर आपके पास रेडीनेस 2030 आया। तो जब आप तैयारी और रक्षा एकीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वह संयुक्त खरीद पहल हो या यूरोपीय रक्षा कोष, मैं जानता हूँ कि ऐसा कहना जल्दबाज़ी होगी– मैं इसे जज नहीं कर रहा क्योंकि यह अभी शुरुआती चरण में है और बहुत ही शुरुआती चरण में है, लेकिन हम पुनर्शस्त्रीकरण के बारे में कैसे बात कर सकते हैं जब पुनर्शस्त्रीकरण पर ही आम सहमति नहीं है?

गुरजीत सिंह: धन्यवाद। ठीक है उमा। पुराने मित्रों, मैं मना नहीं कर सकता और फिर आप, अच्छी बात है, उसके बाद हम अपनी बात शुरू करेंगे।

अज्ञात प्रतिभागी: धन्यवाद सर। आपको इस पैनल की अध्यक्षता करते हुए देखकर खुशी हुई। सभी ने यूरोप के रणनीतिक पुनर्शस्त्रीकरण के बारे में बात की लेकिन मेरा सवला है कि मैं इसके चुनौती वाले हिस्से पर जा रहा हूँ। जब यूरोप को बचाने के लिए एक रणनीतिक रूपरेखा है, तो राष्ट्रीय संप्रभुता, संप्रभुता की अवधारणा का क्या होगा और फिर बहुपक्षीय मंच में अवधारणा की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी का क्या मुद्दा

है? जब इस क्षेत्रीय सुरक्षा की बात आती है तो इसका मतलब अलग होता है। आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के क्या अर्थ होंगे?

गुरजीत सिंह: वहाँ बैठी महिला। अंतिम सवाल। धन्यवाद।

खुशबू शर्मा: सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं खुशबू, जेएनयू से पीएचडी कर रही हूँ। मेरे पास एक सवाल है, प्रोफेसर बावा के लिए। यूरोपीय संघ के सदस्य देश अपने अलग- अलग रणनीतिक हितों को कैसे एक साथ लाएंगे ताकि पुनर्शस्त्रीकरण होने के लिए एक आम रणनीति बनाई जा सके?

गुरजीत सिंह: धन्यवाद। को अब मैं पैनल का रुख करता हूँ कि वे इन सवालों का जवाब दें। कृपया उत्तर संक्षिप्त रखें। जनरल सर वर्मा।

संजय वर्मा: अच्छी बात है, पूछे गए सवालों में एक आम मुद्दा देशों के बीच आम सहमति का था? है ना, धनराशि का बंटवारा, दस्तावेज़ तैयार करना, मंशा बताना, लेकिन क्या वह वैसा रूप ले पाएगा जैसा कि वे चाहते हैं? यह सामान्य सूत्र है। जी हाँ, यह एक समस्या होने वाली है। लेकिन दूसरे कारणों से, जो असल में प्रोफेसर बावा ने भी बताए थे, समस्याएं क्या हैं? इन देसों की प्रवृत्ति अलग है, इन देशों के बीच एक जैसी तकनीक के लिए प्रतिस्पर्धा है, इसलिए समस्याएं होंगी।

मैं एक बुनियादी सवाल उठाता हूँ, ऐसे में जबकि पूरी चर्चा प्रदेश की स्वतंत्रता या किसी ब्लॉक विशेष के खिलाफ सामूहिक रक्षा पर है, रोकथाम के लिए कोई भी सिद्धांत, अवधारणा या दर्शन, वह सवाल भी उठा या युद्ध के लिए, यह भी एक आक्रामक क्षमता से ही पैदा होता है। तो यह केवल सामूहिक रक्षा पर आधारित नहीं हो सकता, क्या वे सामूहिक आक्रमण देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं लेकिन एक हथियार प्रणाली की परिपक्वता और इस पलटाव को बदलने का असली इरादा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या सामूहिक आक्रमण का इरादा भी है, फिर वे एक साथ होंगे, अभी तो वे अलग- अलग हैं, चुनौतियाँ होंगी, इस धन का प्रयोग कैसे किया जाता है।

और बस, एक सेकेंड सर, आपने बताया था कि भारत में किस तरह से बदलाव आएगा, यह बदलाव कैसे होगा, भारत में यह बदलाव कुछ ज़रूरी मुद्दों पर होगा, जो हमारे पास हैं, हमारे पास ठीक- ठाक कुशल

कामगार हैं, ठीक- ठाक किफायती कर्मी हैं, अच्छी विनिर्माण क्षमता है और निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर फिर से उभर रहा है, जो इन देशों के साथ मिल कर भारत में ला सकता है।

गुरजीत सिंह: धन्यवाद। प्रोफेसर बावा।

उम्मू सलमा बावा: मुझे लगता है कि आम सहमति का मुद्दा उठाया गया है और मैंने इसका उल्लेख भी किया है। मेरे ख्याल से यदि आप यह नहीं समझते हैं कि यूरोपीय संघ की संरचना पूरी तरह से एकीकरण के बारे में है, यह कुछ बनाने के लिए राष्ट्रीय मतभेदों को दूर करने के बारे में है, यह समन्वय के बारे में है तो आप मुद्दा भूल जाएंगे। और एक बार जब आप अंतर से आगे बढ़ने की उस सीमा तक पहुँच जाते हैं तो आपको कुछ बहुत ताकतवर मिलता है क्योंकि विश्व में कहीं भी क्षेत्रीय स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा यूरोपीय संघ ने किया है।

लेकिन हाँ, जो चुनौतियाँ आप उस समझ से आगे बढ़ रहे हैं जिसे हम आर्थशास्त्र कहते हैं जहाँ राष्ट्रीय संप्रभुता और हित को रक्षा से जोड़ना कहीं अधिक सरल था, जो एक स्तर पर भूगोल को बहुत अलग तरह की चुनौतियों के सामने लाता है। इसलिए भूगोल राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा संकट पैदा नहीं करता है लेकिन जैसे ही आप साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कदम रखते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश कहाँ है।

मुझे लगता है कि परंपरागत संकट और नए हाइब्रिड संकटों को देखने के इन दो तरीकों को मिलाने से एक मौका मिलेगा, जिसका यूरोप ने पहली बार लाभ उठाया है। बात यह है कि पूरे यूरोप के नेतृत्व को लगातार मिलकर इस बात की पहचान करनी होगी कि यह एक रणनीतिक क्षण है या जिसे मैं बदलाव का समय कहूँगी। बीते तीन वर्षों में बड़े दस्तावेज़ सामने आए हैं, इससे पता चलता है कि राजनीतिक मंशा थी। यह आधी जंग जीतने जैसा है। क्योंकि यदि आपकी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है तो आप कोई दस्तावेज़ बाहर नहीं ला सकते।

तो बात यह है कि रक्षा औद्योगिक नीति, पुर्शस्त्रीकरण यूरोप और यूरोप रेडिनेस 2030 सभी एक साथ आने और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सामूहिक कार्रवाई की तरफ ले जाने की ओर संकेत देते हैं। फिर

जनरल वर्मा ने जो कहा, वह बात होगी कि रक्षा पहला मुद्दा है। उन्होंने अभी तक हमले की पहचान नहीं की है। यह कुछ ऐसा है जो आगे चलकर होगा। इसके लिए बहुत ज्यादा सैन्य क्षमता की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले, यूरोपीय तैयारी पर ज़ोर देने के लिए ज़मीन तैयार करना है और एक बात जो एलेक्सी ने कही, पहली बार, यह रक्षा के क्षेत्र में अटलांटिक योगदान और रक्षा में यूरोपीय योगदान के बीच फर्क करने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल से यह एक बहुत, बेहद ज़रूरी फर्क है जिसे हमें बनाए रखना होगा।

गुरजीत सिंह: धन्यवाद। प्रोफेसर ज़खारोव, कृपया दो मिनट में उत्तर दे दें।

एलेक्सेई ज़खारोव: मैं रक्षा क्षमता को मजबूत करने के भविष्य की राह पर यूरोपीय देशों में आम सहमति न होने की बात से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि यूरोपीय समाज अभी इस सैन्य पुश का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम अब अलग- अलग देशों के स्तर पर अलग- अलग प्रयास देख रहे हैं जो अभी तक यूरोपीय संघ के स्तर तक नहीं पहुँचा है। हाँ, अटलांटिक पार के संबंधों में बहुत सारी अनिश्चितताएं इस पुनर्शस्त्रीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद नहीं करती हैं।

और बहुध्रुवीय विश्व में रूस के बारे में बस एक छोटी सी बात। मेरे ख्याल से कोशिश यह है कि वहाँ ज्यादा सक्रिए रूप से उपस्थिति रहा जाए। रूस की कोशिश ग्लोबल साउथ के देशों को अपनाने की, असल में बहुत सक्रिए रही है क्योंकि मुझे लगता है कि रूस और पश्चिमी शक्तियां दोनों ही समझती हैं कि आख्यान के लिए लड़ना और उसके समर्थन के लिए लड़ना वाकई जरूरी है, भले ही वे सकारात्मक रूप से तटस्थ हों। इसलिए मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में रूस की मौजूदगी ज्यादा रही है, कम- से- कम मेरे नज़रिए से तो ज्यादा। लेकिन यह बेशक भविष्य की बहस पर निर्भर है। धन्यवाद।

गुरजीत सिंह: धन्यवाद। एक बार फिर सवालों के जवाब सुनकर मेरे जेहन में यूरोप में घटी किसी और घटना पर चला गया। वह घटना थी- जब अमेरिकियों ने इराक और अफ़गानिस्तान में सेना भेजी, तो कई यूरोपीय देशों ने सैनिक भेजे और उन्हें नुकसान भी हुआ। उनमें से एक डेनमार्क भी है। अगली बार, मुझे नहीं लगता कि वे इन सब में शामिल होंगे। तो यह यूरोपीय और अटलांटिक प्रतिक्रिया के बीच का अंतर है। स्पष्ट है, मुझे संदेश मिला है कि इस बार हमारे सैनिक नहीं जाएंगे, हमारे मकसद के लिए नहीं।

मुझे लगता है कि यह बात मेरे दिमाग में घर कर गई है। मेरे पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है लेकिन यह कुछ ऐसा है जो मैंने सुना है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मुझे माफ करें क्योंकि मैंने निर्धारित समय से पांच मिनट अधिक का समय ले लिया लेकिन हमें आमंत्रित करने का बहुत-बहुत धन्यवाद। आईसीडब्ल्यूए, हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद।

अज्ञात वक्ता: मुझे लगता है कि हम सब प्रोफेसर बावा की इस बात से सहमत होंगे की यूरोप एक नाज़ुक मोड़ पर है। आईसीडब्ल्यूए की ओर से, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और वक्ताओं का बहुत- बहुत धन्यवाद करता हूँ। आईसीडब्ल्यू की कार्यवाहक महानिदेशक सुश्री नूतन कपूर महावर और परिषद में शोध निदेशक सुश्री निवेदिता रे को उनके सतत सहयोग और मार्गदर्शन के लिए मेरा विशेष धन्यवाद।

मैं अपने सभी सहकर्मियों और दर्शकों को भी आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईसीडब्ल्यू के शोध कार्यों, कार्यक्रमों, आउरीच कार्यक्रमों एवं प्रकाशनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट और ट्विटर, लिंक्डइन, यू-ट्यूब और फेसबुक पर सोशल मीडिया हैंडल्स देखें। धन्यवाद। कृपया उपकक्ष में हमारे साथ जलपान करें। आप सभी का बहुत- बहुत धन्यवाद।

प्रतिभागियों की सूची:

सुश्री नूतन कपूर महावर, कार्यवाहक महानिदेशक और अपर सचिव, आईसीडब्ल्यूए

राजदूत गुरजीत सिंह, जर्मनी, इंडोनेशिया, इथियोपिया, आसियान और अफ्रीकी संघ में भारत के पूर्व राजदूत और आईआईटी, इंदौर में मानद प्रोफेसर

लेफ्टिनेंट जनरल संजय वर्मा, हथियार और उपकरण के पूर्व महानिदेशक, सेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और सामरिक एवं रक्षा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के प्रतिष्ठित फेलो

प्रोफेसर उम्मू सलमा बावा, अध्यक्ष और जीन मोनेट चेयर, सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू और स्पेशल सेंटर फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज, जेएनयू की अध्यक्ष

डॉ. एलेक्सेई ज़खारोव, ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली के स्ट्रैटेजिक स्टडीज़ प्रोग्राम के फेलो

-x-x-x-